(ग) इस संबंध में प्रत्येक राज्य को केन्द्र सरकार ने अब तक कितनी राहत-राशि प्रदान की है और बाढ़ के कारण उत्पन्न स्थिति का मुकाबला करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): (क) से (ग) देश के विभिन्न भागों में हाल ही में आई बाढ़ के कारण हुई जान तथा माल की हानि की सीमा और वर्ष 1996-97 में प्रभावित राज्यों को आपदा राहत निधि के केन्द्रीय अंश के तौर पर निर्मुक्त निधियों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। (**नीचे देखिए**) राज्य सरकार क्षतिग्रस्त हुई सार्वजनिक सम्पत्ति की मरम्मत तथा पुनरूद्धार के लिए सभी आवश्यक राहत प्रदान करती रही हैं तथा उपाय भी करती रही हैं।

विवरण

देश के विभिन्न भागों में हाल ही में आई बाढ़ के कारण हुई जान-माल की हानि की सीमा और वर्ष 1996-97 में प्रभावित राज्यों को आपदा-राहत निधि से केन्द्रीय अंश के तौर पर निर्मुक्त निधियों को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं॰	राज्य	प्रभावित क्षेत्र (लाख है॰ में)	मृत व्यक्तियों की संख्या	प्रभावित फसल क्षेत्र (लाख है॰ में)	नष्ट हुए मकानों की संख्या	1996-97 के लिए निर्मुक्त आपदा राहत निधि का केन्द्रीय अंश (रु॰ करोड़ में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	0.15	100	0.15	21517	46.570*
2.	अरूणाचल प्रदेश	-	02	-		2.640
3.	असम	4.61	12	1.82		18.755
4.	गुजरात	18.22	54	0.03	50849	52.350
5.	हरियाणा	0.33	14	0.15	12083	9.395
6.	जम्मू एवं कश्मीर	0.58	39	0.45	17049	7.390
7.	कर्नाटक	-	106	-	3248	15.695
8.	केरल	0.28	32	0.21	10734	20.775**
9.	महाराष्ट्र	-	114		1611	25.575
10.	पंजाब	-	4			20.305
11.	राजस्थान	3.28	111	0.46	104513	100.710
12.	तमिलनाडु	0.05	54	0.05	38296	22.255
13.	त्रिपुरा	-	7			1.685
14.	उत्तर प्रदेश	1.26	51	0.62	21589	46.920
15.	पश्चिम बंगाल	-	12		150	9.245
	योग :	28.76	747	3.94	281684	

*1995-96 के दौरान अग्रिम तौर पर जारी एक किश्त शामिल है।

**1995-96 के दौरान अग्रिम तौर पर जारी किया गया।

Suspension of the system of "Telescopic Fare"

692. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the MINISTER OF RAILWAYS be pleased to state:

(a) the reasons for the suspension of the system of "Telescopic Fare" in south Central Railways in Andhra Pradesh;

(b) whether Railways are aware that "telescopic fare" is the rule in all other railway system in the world; and

(c) the steps proposed to be taken to revive the system of "telescopic fare" for the benefit of passengers?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SATPAL

MAHARAJ): (a) to (c) Passenger fares are telescopic and are applicable uniformally on all the railways including South Central Railway. However, the telescopic benefit has been withdrawn with effect from 21.7.1994 on tickets issued for extension of journeys.

Transfer of Catering/Vending contracts

693. SHRI JALALUDIN ANSARI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that as per the policy of the Government the Catering/Vending contracts can automatically be transferred to the legal heir of the deceased contractor; and

(b) if so, what are the detailed guidelines in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SATPAL MAHARAJ): (a) and (b) As per policy, in the event of death of licencee of a catering/vending unit, the licence can be transferred in the name of legal heir for the unexpired period of contract.

रेल अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें

694. **श्री राघवजी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1995 के दौरान मंत्रालय को रेल अधिकारियों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और दुव्यवहार की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है;

(ख) इनमें से ऐसी कितने शिकायतें है जिनके संबंध में आज तक की स्थिति के अनुसार समाधानकारक उत्तर संबंधित संसद सदस्यों को नहीं दिए गए हैं; और

(ग) उत्तर भेजने में हुए विलम्ब के क्या कारण है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) 131

(ख) 56

(ग) शिकायतों की जांच पड़तालों में फील्ड इकाइयों के रिकार्ड की संवीक्षा तथा अंत: ग्रस्त पाए गए अधिकारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त करना शामिल हैं, जिनमें बहुत समय लगता है। 56 लम्बित पड़ी शिकायतों में से 4 फर्जी नामों से पायी गई, एक मामले में संसद सदस्य की मृत्यु हो गई थी, जब कि 13 अन्य मामलों में जांच पड़ताल की गई थी किंतु रेल मंत्री के पद परित्यागने के कारण उत्तर नहीं भिजवां सके थे। 32 मामले जांच पड़ताल के अधीन है, जबकि 6 मामले जांच पड़तालों के बाद केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह के लिए लम्बित पड़े हैं।

Steps taken to check fake Universities

695. SHRI RAMDAS AGARWAL:
DR. D. VENKATESHWAR RAO:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the mushroom growth of "fake" universities and Vishwavidalayas which are functioning all over the country in contravention of the provisions of the University Grants Commission Act, as reported in the Hindustan Times dated 3rd July, 1996;

(b) if so, the details thereof and since when such institutions are functioning, State-wise; and

(c) what preventive measures Government propose to take or prevail upon UGC to ensure that only such universities are allowed to function who have legal entity to call themselves as "universities" or "Vishwavidyalayas" and to award degree with details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPTT. OF EDUCATION IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI MUHI RAM SAIKIA): (a) and (b) Yes, Sir. According to the information furnished by the University Grants Commission (UGC), the number of institutions styling themselves as universities is 20 but Association of Indian Universities (AIU) have informed that there are 36 self-styled universities. There are 20 universities common to both the lists. While, a State-wise list of fake universities as circulated by UGC is enclosed as statement (see below), it is difficult to say since when these self-styled universities are functioning.

(c) The UGC, AIU and the Monopolies and Restricitive Trade Practices Commission (MRTPC) keep watch on the existence of fake universities functioning in violation of the UGC Act, 1956. As soon as information about the existence of fake universities comes to the notice of UGC, promoters/office-bearers of such self-styled/fake universities are informed of the relevant provisions of the UGC Act. They are also advised to disassociate the use of expression "University" and also stop awarding